ऑल इंडिया उर्दू कान्वेंशन : रांची 6-7 मई 2023

झारखंड की राजधानी रांची में जनवादी लेखक संघ ने दो दिवसीय 'ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन' आयोजित किया जिसमें मुल्क भर के हिंदी और उर्दू ज़बान के बड़े अदीब, नक्क़ाद और दानिश्वर मौजूद रहे। कन्वेंशन का अहम मौज़ू 'हिंदी और उर्दू के तख़लीक़ी रिश्ते : माज़ी और हाल' था। इस अहमतरीन कन्वेंशन में न सिर्फ़ उर्दू ज़बान की तरक़्क़ी, उर्दू की मौजूदा सूरत-ए-हाल और उसे फ़रोग़ देने के लिए नयी तजवीज़ों पर संजीदा बातचीत हुई, बल्कि इस ख़ूबसूरत ज़बान की बेहतरी के हक़ में कई अहम प्रस्ताव भी पेश किये गये। रांची स्थित 'सामाजिक विकास केंद्र' (एसडीसी) के सभागार में दो दिन में कुल आठ सेशन हुए। जिसमें कई दिलचस्प सब्जेक्ट पर बात हुई। मसलन 'समकालीन उर्दू अदब के रुजहानत और सरोकार', 'उर्दू सहाफ़त आज और कल'। इसके अलावा 'तहरीक-ए-आज़ादी', 'तरक़्क़ीपसंद तहरीक', 'सिनेमा और रंगमंच में उर्दू का क्या योगदान रहा'?, इन मौज़ूआत पर भी तफ़सील से चर्चा हुई। प्रोग्राम ख़ासा कामयाब रहा। इस कन्वेंशन की ख़ासियत, नयी पीढ़ी का इससे जुड़ना रहा। चार दर्जन से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स ने इसमें अपना पर्चा पढ़ा। जिसमें लड़कियों की तादाद अच्छी ख़ासी थी। दोनों ही दिन रांची और आसपास के शहरों के सैकड़ों सामईन के अलावा धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, पलामू हज़ारीबाग़ के साहित्य प्रेमियों ने इसमें शिरकत कर इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया। कन्वेंशन में उर्दू ज़बान के बड़े अदीबों के साथ हिंदी के जाने-माने लेखक आलोचक चंचल चौहान, रविभूषण, संजीव कुमार, बजरंग बिहारी तिवारी, नलिन रंजन सिंह, ख़ालिद अशरफ़,, सफ़दर इमाम कादरी,, अतहर फ़ारुक़ी,, असलम परवेज़,, मुख़्तार ख़ान और कहानीकार रणेंद्र, पंकज मित्र आदि ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में वरिष्ठ मार्क्सिस्ट लीडर - सोशल वर्कर सुभाषिनी अली की भी भागीदारी रही।

पहला सत्र उद्घाटन सत्र था जिसकी अध्यक्षता जनवादी लेखक संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.चंचल चौहान ने की, तो वहीं इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू (हिंद) के जनरल सेक्रेटरी डॉ.अतहर फ़ारुक़ी ने किया। स्वागत समिति के चेयरमैन डॉ.फ़िरोज़ अहमद ने अपने स्वागत भाषण में पुरज़ोर तरीक़े से यह प्रस्तावना रखी, उर्दू किसी एक क़ौम की ज़बान नहीं, हम सभी की ज़बान है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ से ही जम्हूरियत क़ायम रहेगी। अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू (हिंद) के जनरल सेक्रेटरी डॉ.अतहर फ़ारुक़ी ने इस सेशन में एक अलग ही बुनियादी सवाल उठाते हुए कहा, उर्दू ज़बान को यदि हमें बचाना है, तो हमें अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देनी होगी। तालीम से ही उर्दू का मसला सुधरेगा। उसके साथ इंसाफ़ होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, स्थानीय भाषा के साथ-साथ उर्दू का भी विकास होना चाहिए। दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव, समालोचक संजीव कुमार ने कहा, जलेस की उर्दू भाषा के प्रति हमेशा पक्षधरता रही है। उसने अपने हर अधिवेशन में उर्दू ज़बान के पक्ष में ज़रूरी प्रस्ताव पेश किये हैं। जलेस के मुखपत्र *नया पथ* ने उर्दू अदीबों पर कई ऐतिहासिक अंक निकाले हैं। वरिष्ठ आलोचक चंचल चौहान ने उर्दू के प्रति अपनी चिंताओं को साझा करते हुए कहा, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हमले उर्दू पर हुए हैं। जनवादी लेखक संघ की उर्दू पर स्पष्ट लाइन है। 'हिंदुस्तान में उर्दू की हिफ़ाज़त और फ़रोग़ देने की लड़ाई, जम्हूरियत को बचाने की लड़ाई है। उम्मीद है कि यह कन्वेंशन उर्दू की तरक़्क़ी में मददगार साबित होगा'। जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष समालोचक डॉ.रविभूषण, डॉ.अली इमाम ख़ान, साहित्य अकादमी कार्यकारिणी के सदस्य प्रसिद्ध साहित्यकार और रंगकर्मी महादेव टोप्पो, ज़ेवियर कुजूर और ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन के संयोजक एम. ज़ेड ख़ान ने भी इस सेशन में अपने ख़यालात का इज़हार किया। इस सत्र में बिरादराना संगठनों प्रलेस, जसम के संदेश वाचन के अलावा स्मारिका और उर्दू के अज़ीम अफ़सानानिगार कृष्ण चंदर के चर्चित रिपोर्ताज, 'पौदे' का लोकार्पण मुख्य अतिथि और बाक़ी अतिथियों ने किया। यह किताब साल 1947 में उर्दू ज़बान में शाए हुई थी सात दशक बाद 'पौदे' का हिंदी लिप्यंतरण आया है। लेखक-पत्रकार जाहिद ख़ान ने लिप्यंतरण किया है।

कन्वेंशन का पहला सेशन 'हिंदी और उर्दू के तख़लीक़ी रिश्ते: माज़ी और हाल' विषय पर था जिसकी अध्यक्षता डॉ.अली इमाम ख़ान ने की। वहीं डॉ.मोहम्मद अय्यूब (रांची) और डॉ.संत राम (कोलकाता) ने इस सब्जेक्ट पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। सेशन में रिसर्च स्कॉलर्स ने भी अपने पर्चे पढ़े। दूसरा वैचारिक सत्र 'समकालीन उर्दू अदब के रुजहानात और सरोकार' विषय पर था जिसकी सदारत डॉ.अतहर फ़ारुक़ी ने की, तो डॉ.नजमा रहमानी (नयी दिल्ली), डॉ.सफ़दर इमाम कादरी (पटना) और डॉ.शहाब ज़फ़र आज़मी (पटना) ने इस सेशन में अपने विचार रखे। डॉ.नजमा रहमानी का कहना था, नयी पीढ़ी को जब उर्दू की तालीम लेने और अपनी ज़बान को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो अदब की तख़लीक़ कैसे होगी? आलम यह है कि पीएचडी स्कॉलर्स की ज़बान में भी दिक्क़तें

हैं। समाज में बढ़ती असहिष्णुता ने भी उर्दू को काफ़ी नुक़सान पहुंचाया है। इस दिन का तीसरा और आख़िरी सत्र उर्दू पत्रकारिता को लेकर था जिसका विषय 'उर्दू सहाफ़त : आज और कल' था। इस सेशन की अध्यक्षता सैयद रेहान ग़नी (पटना) ने की, तो असलम परवेज़ (मुंबई), बदरे वफ़ा शैदाई (पटना) और डॉ.जमशेद कमर (रांची) ने इस महत्वपूर्ण मौज़ू पर अपनी बात रखी। सभी ने उर्दू सहाफ़त की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अपनी चिंताओं का इज़हार करते हुए, इसे सुधारने के लिए अपनी ओर से कुछ अहम तजवीजें भी दीं। कार्यक्रम का शानदार संचालन मुख़्तार ख़ान (मुंबई) ने किया। कन्वेंशन के दूसरे दिन के पहले सत्र का विषय 'हिंदुस्तानी अदब में उर्दू की देन' था। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.रविभूषण ने कहा, उर्दू शायरी इश्क़ और इंक़लाब की शायरी है। प्रोफ़ेसर बजरंग बिहारी तिवारी ने कहा, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालमी आदि भाषाओं पर उर्दू की छाप साफ़' दिखायी देती है। संस्कृत में कई उर्दू पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। परमानंद शास्त्री ने ग़ालिब की ग़ज़लों का अनुवाद किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफ़ेसर ख़ालिद अशरफ़ ने कहा, मुल्क में उर्दू की तरक़्क़ी औरंगज़ेब के बाद हुई। उर्दू ज़बान में पचहत्तर फ़ीसदी अल्फ़ाज़, हिंदुस्तानी अल्फ़ाज़ हैं। उर्दू ज़बान के जाने-माने दानिश्वर डॉ.अली इमाम ख़ान का कहना था, उर्दू अदब इंसान दोस्ती और भाईचारे का मज़मूआ है। 'तरक़्क़ी पसंद तहरीक और उर्दू' विषय पर हुए सत्र की अध्यक्षता करते हुए आलोचक डॉ.चंचल चौहान ने कहा, 'हर आंदोलन के बनने और ख़त्म होने के पीछे सामाजिक वर्गों की हलचल होती है। प्रगतिशील आंदोलन भी पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के कशमकश की पैदावार है। उर्दू अख़बार और अदीब अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी मुखर रहे, उन्होंने ही प्रगतिशील आंदोलन के गठन में अहम रोल अदा किया।' जर्नलिस्ट समीना ख़ान (लखनऊ) ने कहा, उर्दू अदब पर तरक़्क़ीपसंद तहरीक की वाजेह छाप दिखलायी देती है। कथाकार रणेंद्र (रांची) ने अपने चर्चित उपन्यास 'गूंगी रुलाई का कोरस' में से कई उद्धरणों का हवाला देते हुए कहा, संत कवियों, संगीतकारों और गायकों ने जो आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया है, उसे फ़रामोश नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की एक मिली-जुली संस्कृति है। इस सांझा संस्कृति को बचाने की ज़िम्मेदारी हम सभी की है। लेखक-पत्रकार जाहिद ख़ान ने जिनका तरक़्क़ीपसंद तहरीक पर बेजोड़ काम है, कहा, उर्दू ज़बान को यह मर्तबा या गौरव हासिल है कि तरक़्क़ीपसंद तहरीक की इब्तिदा उर्दू अदीबों ने की। आगे चलकर यह तहरीक मुल्क की दूसरी ज़बानों तक पहुंची। तरक़्क़ीपसंद तहरीक से जुड़े अदीबों ने मुल्क की आज़ादी के हक़ में जमकर लिखा, ज़रूरत पड़ी तो बंटवारे, सामंतवाद, साम्राज्यवाद और फ़ासिज़्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गये। उन्होंने कहा, आज एक बार फिर हमारे सामने यह ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है। साम्राज्यवाद चेहरा बदलकर और फ़ासिज़्म खुलकर हमारे सामने है। देश के *संविधान* और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सत्ता में बैठे लोग ही सबसे ज़्यादा हमला कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारी यह इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कलम को हथियार बनायें। अवाम को उसके अधिकारों के जानिब बेदार करें। तभी हमारा अदबी फ़र्ज़ पूरा होगा। इस सेशन का उम्दा संचालन कवि- आलोचक डॉ.नलिन रंजन सिंह (लखनऊ) ने किया।

कन्वेंशन का तीसरा और आख़िरी वैचारिक सत्र 'उर्दू इदारों की सूरते हाल' विषय पर था जिसकी अध्यक्षता करते हुए सीपीएम पोलित ब्यूरो की मेंबर, पूर्व सासंद सुभाषिनी अली ने कहा, 'उर्दू को किसी विशेष धर्म या वर्ग से जोड़ना ग़लत है। यह विशुद्ध रूप से भारतीय भाषा है। जो यहीं जन्मी और पली-बढ़ी। यहीं से दुनिया भर में फैली। आज उर्दू को धर्म से जोड़कर, समाप्त करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने कहा, यदि नयी शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो गयी, तो उर्दू का वजूद ख़त्म हो जायेगा। क्योंकि इस नीति में उर्दू ज़बान को कोई तरजीह नहीं दी गयी है। जब उर्दू स्कूल बंद हो जायेंगे, नये स्कूल खुलेंगे नहीं, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, तो नयी पीढ़ी उर्दू ज़बान से दूर हो जायेगी। यह ख़तरनाक स्थिति होगी। हमें सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ भाषा - संस्कृति को बचाने की भी मुहिम चलानी होगी। सोशल एक्टिविस्ट नाइश हसन (लखनऊ), जो अपने इंक़लाबी तेवरों के लिए जानी जाती हैं ने कहा, किसी भी ज़बान को फ़रोग़ देने में उसके बोलने वालों के साथ ही हुकूमत का भी अहम किरदार होता है। एक ऐसा वक़्त जब हमारे चारों तरफ़ बेयक़ीनी का माहौल हो, इरादतन किसी ज़बान को कुचला जा रहा हो, सिर्फ़ इस बिना पर कि उसके बोलने वालों में एक ख़ास मज़हब के लोगों की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश, जहां उर्दू को स्टेट की सेकंड लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, वहां के सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब है। यह दर्जा, महज काग़ज़ी है। बाक़ी सूबों के हालात भी इस मामले में बेहतर नहीं। इस सेशन में डॉ.अली इमाम ख़ान, डॉ.ख़ालिद अशरफ़ और डॉ.सफ़दर इमाम कादरी ने भी अपनी बात रखी। एक विशेष सत्र रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने आलेख में से प्रमुख बिंदुओं का पाठ किया। कन्वेंशन का आख़िरी सत्र 'मीडिया और थियेटर में उर्दू' सब्जेक्ट पर था जिसकी अध्यक्षता कथाकार पंकज मित्र ने की। शाम को मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय कवि और शायरों ने अपने बेहतरीन कलाम का पाठ किया।

कन्वेंशन के दौरान कई बहसें ऐसी भी उठीं जो उर्दू बोलने वालों के दरमियान कई सवाल खड़े करती हैं। मसलन उर्दू के साथ तमाम सरकारी और निजी इदारों का सुलूक कैसा है? उर्दू ज़बान की बेहतरी के लिए वे जो कोशिशें कर रहे हैं, क्या सही दिशा में हैं? या फिर इन इदारों द्वारा उर्दू के नाम पर सिर्फ़ ख़ानापूर्ति की जा रही है। बहरहाल, मुस्लिम बहुल आबादी वाले सूबों उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और महाराष्ट्र में भी आज आलम यह है कि उर्दू ज़बान के तईं निराशा और उदासीनता का माहौल है। यदि इसकी तह में जायें, तो राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी और आधिकारिक निष्क्रियता दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। झारखंड का शुमार मुल्क के उन सूबों में है, जहां उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही राज्य के सभी 24 ज़िलों की क्षेत्रीय भाषा की फ़ेहरिस्त में भी उर्दू ज़बान शामिल है। बावजूद इसके यहां उर्दू ज़बान की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं। उर्दू के साथ यहां सौतेला बर्ताव किया जाता रहा है। ज़रूरत के मुताबिक़ उर्दू टीचरों की नियुक्ति से लेकर, राज्य उर्दू अकादमी का गठन यहां बरसों से लंबित है। झारखंड अकेले की बात क्या करें, तल्ख़ हक़ीक़त यह है कि उर्दू को किसी भी सूबे में वाजिब सरकारी मदद नहीं मिल रही है। उर्दू के जानिब हुकूमतों का रवैया सौतेला ही रहा है। अलबत्ता कई सूबों में एक उर्दू अकादमी ज़रूर है जिसका इस्तेमाल हुकूमतें अपने मनचाहे लेखकों और शायरों को नवाजने के लिए करती हैं। आम अवाम में उर्दू को कैसे बढ़ावा मिले?, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। उर्दू पत्र-पत्रिकाओं को मिलने वाले सरकारी इश्तिहारों में आयी कमी ने इस मीठी ज़बान का और भी नुक़सान किया है। गोयाकि कई सूबों में तो उर्दू अख़बारों के लिए सरकारी इश्तिहारों पर भी पाबंदी है। देखते-देखते उर्दू के लाखों की तादाद में छपने वाले अख़बार और पत्रिकाएं बंद हो गयीं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं।

प्रोग्राम के आख़िर में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कई प्रस्ताव पढ़े गये और उन्हें सब की रज़ामंदी से पारित किया गया।

प्रस्ताव–1 : झारखंड उर्दू अकादमी की स्थापना के लिए

झारखंड राज्य 15 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके पूर्व से ही आज के झारखंड और पूर्व के बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। साथ ही झारखंड में उर्दू भाषाभाषी लोगों का बड़ा तबक़ा बसता है। झारखंड एक बहुभाषी राज्य है और उर्दू की यहां विशिष्ट एवं अलग पहचान है। यहां के सभी स्टेट विश्वविद्यालयों में उर्दू के विभाग हैं जहां शिक्षण, सृजन और शोध का सिलसिला लगातार जारी है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में झारखंड की अपनी विशिष्ट पहचान है, लेकिन उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास तथा उर्दू के साहित्यकारों के प्रोत्साहन और सहयोग के लिए कोई संस्था नहीं है जबकि भारत के बहुत सारे राज्यों में उर्दू अकादमी स्थापित की गयी हैं। अतः यह ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन झारखंड सरकार से मांग करता है कि 'झारखंड उर्दू अकादमी' की स्थापना यथाशीघ्र की जाये तथा उर्दू के विकास को सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्ताव - 2 : उर्दू की पढ़ाई और उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था।

भारत के कई राज्यों में उर्दू पढ़ने वालों और उर्दू माध्यम से पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की कमी है। उदाहरण स्वरूप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड में उर्दू का विभाग नहीं है। यह स्थिति कई राज्यों में है। महाराष्ट्र में 2009 में स्वीकृत क़ानून के तहत उर्दू माध्यम के स्कूलों को सरकारी ग्रांट नहीं मिलती है। यह शिक्षा के मामले में भेदभाव को दर्शाता है, जो असंवैधानिक है। इसके अलावा उर्दू शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पर रिक्त हैं, चाहे स्कूल हों या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। स्कूल में उर्दू शिक्षक के पद पर दूसरे विषय के शिक्षक की नियुक्ति के मामले भी सामने आये हैं। उर्दू में पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा में उत्तर उर्दू में लिखने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा ही मामला बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद का है। जबकि झारखंड के दूसरे विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था पहले से है। नतीजा यह है कि उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले अपने आपको भेदभाव का शिकार मानते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है। अतः यह ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन संबंधित संस्थान, सरकारों और ज़िम्मेदार व्यक्तियों से मांग करता है कि-

1. स्कूल (सरकारी, प्राइवेट) से लेकर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय (स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट) तक उर्दू की पढ़ाई की उचित व्यवस्था की जाये।
2. उर्दू मीडियम और उर्दू स्कूल को सरकारी ग्रांट प्रदान की जाये।
3. उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाये तथा उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति की जाये।
4. उर्दू में पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध करायी जायें।
5. परीक्षा में उर्दू में उत्तर लिखने की व्यवस्था तत्काल की जाये।
6. उर्दू अनुवादक तथा उर्दू सहायक, अनुवादक के लिए पदोन्नतिकी व्यवस्था की जाये।

7. सेवा काल में उर्दू सीखने वालों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान हो।

प्रस्ताव–3 : उर्दू के उत्थान एवं विकास के लिए स्थापित संस्थानों में बेहतर एवं समुचित व्यवस्था हो

भारत में उर्दू भाषा एवं साहित्य के उत्थान एवं विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कई संस्थान स्थापित किये गये हैं जिनमें 'नेशनल काउंसिल फ़ॉर प्रमो़शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (एनसीपीयूएल) तथा कई राज्यों में 'उर्दू अकादमी' व 'उर्दू डायरेक्टरेट' विशेष महत्व के हैं। लेकिन ये संस्थान उपेक्षा का शिकार हैं। इन संस्थानों में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी के पद वर्षों तक रिक्त पड़े रहते हैं और इन पर नियुक्ति नहीं होती है या विलंब से होती है जिसके कारण उनके कार्यकलाप पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मिसाल के लिए 'बिहार उर्दू अकादमी' और 'दिल्ली उर्दू अकादमी को लिया जा सकता है। कुछ ऐसी ही हालत 'उर्दू डायरेक्टरेट' और 'नेशनल काउंसिल फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज' की भी बनी रहती है। उनके बेहतर और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, उनकी बेहतर व्यवस्था एवं प्रबंधन की दरकार है। जिसके लिए लोकतांत्रिक तौर-तरीक़े और प्रतिनिधित्व समय की मांग है। यह ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से मांग करता है कि उर्दू के उत्थान एवं विकास के लिए स्थापित संस्थान यथा उर्दू अकादमी, उर्दू डायरेक्टरेट, 'नेशनल काउंसिल फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज में ज़िम्मेदारी के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति कर, उन्हें प्रभावी एवं कारगर बनाया जाये ताकि सही अर्थों में ये संस्थान उर्दू की सेवा के लक्ष्य को पूरा कर सकें। साथ ही इन संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाया जाये। यह कन्वेंशन यह भी मांग करता है कि झारखंड में उर्दू डायरेक्टरेट की स्थापना की जाये। उर्दू भाषा एवं साहित्य के संबंध में सरकारी नीति एवं कार्यक्रम को लागू करने के लिए 'उर्दू कार्यान्वयन आयोग' और 'उर्दू कार्यान्वयन सलाहकार बोर्ड' की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया आरंभ की जाये।